ग्रहमत मुक्तनाद

वर्ष:4 अंक:1-3 जनवरी-मार्च 2002

ई डब्लयू सईद
न की भिड़ंत

प्रसाद
दुनिया,
ाज्यवाद और
ख्वाद की

गताडे
की
यां: एक
वलोकन

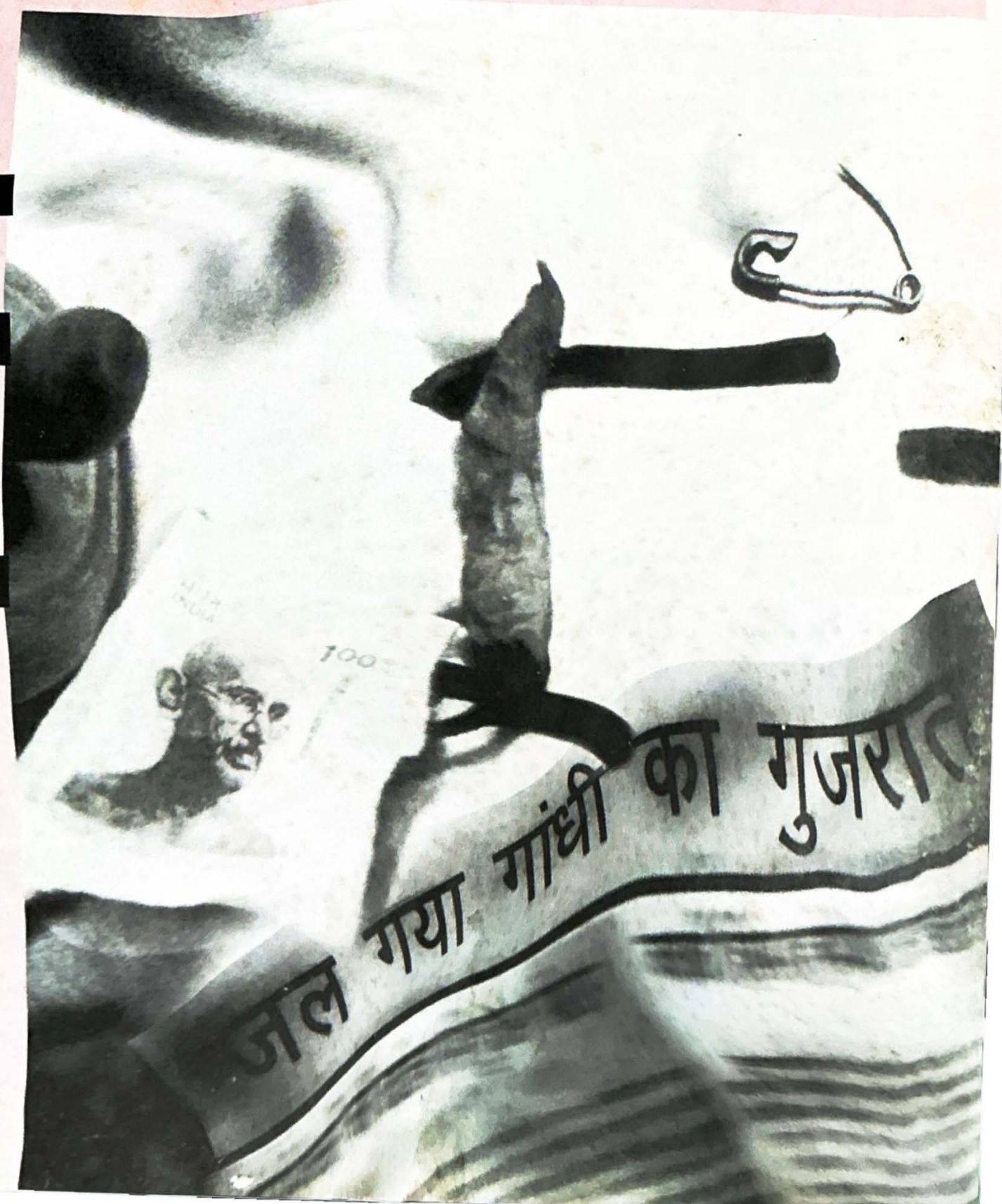

सहमत मुक्तनाद

वर्ष: 4 अंक : 1 - 3

जनवरी – मार्च 2002

यह अंक 30 रु.

वार्षिक सदस्यता 150 रु.

संरक्षक मण्डल:

भीष्म साहनी

इरफान हबीब

सुवीरा जायसवाल

हबीब तनवीर

संपादक मण्डल:

के. एन. पणिक्कर

राजेन्द्र प्रसाद

अनिल चौधरी

राजेन्द्र शर्मा

शबनम हाशमी

संपादकीय व प्रबन्ध कार्यालय:

सहमत

8 विट्ठलभाई पटेल हाऊस

रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 3711276, 3351424

आवरण चित्र: पार्थिव शाह की कलाकृति से है।

संपादन और प्रकाशन पूर्णत: अवैतनिक टिप्पणियों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनसे संपादक/प्रकाशक का सहमत होना जरूरी नहीं है।

सारे भुगतान चैक या बैंक ड्राफ्ट से **सहमत** के नाम से किए जाएं।

अनुक्रम

1 **संपादकीय**
खामोश! हिंदू राष्ट्र बन रहा है

4 मैं शांति के लिए बातचीत करना चाहता हूं - यासर अराफात

6 **ए जी नूरानी**
अयोध्या प्रकरण, भूमि और कानून के सवाल

9 शिलान्यास से पहले हुआ समझौता

10 **अर्जुन देव**
इतिहास पर सांप्रदायिक आघात

14 भारत के दोनों महान सम्राट गैर-हिंदू थे

17 **राजू रंजन प्रसाद**
इतिहास के हिंदुत्ववादी औजार बनाने का अभियान

20 **सूरज देव सिंह और कुसुम लता**
क्या भारत फासीवाद के कगार पर है?

24 **जवरीमल्ल पारख**
मीडिया की नजर में विधानसभा चुनाव

28 **सी पी चंद्रशेखर**
बजट 2002-03: फिर मौका गंवाया

31 **अमित सेनगुप्त**
नयी दवा नीति का हमला

34 **सुभाष गाताडे**
महाड की स्मृतियां - एक पुनरावलोकन

40 **एजाज़ अहमद**
पाकिस्तान: परीक्षा की घड़ी

46 **राजेंद्र शर्मा**
पाकिस्तान एक नये राष्ट्रवाद की ओर मगर हम...

49 **एडवर्ड डब्ल्यू सईद**
अज्ञान की भिंड़त

52 **विजय प्रसाद**
अरब दुनिया, साम्राज्यवाद और नासरवाद की हत्या

58 **राबर्ट फिस्क**
किला अब्दुल्ला में फिस्क ने झेला अफगान उत्पीड़ितों का विक्षोभ

61 **रामसुजान अमर**
भूमंडलीकरण और साम्राज्यवाद

64 राघव
अफगानिस्तान की खोह और खंदक

66 **जॉन पिल्जर**
लड़ाई आतंकवाद से या सारी दुनिया से

69 **प्रभात पटनायक**
व्यापार, विकास और विश्व अर्थव्यवस्था

72 **जयति घोष**
मर्ज कुछ, दवा कुछ

75 **श्रीकांत मिश्र**
लोभ और स्वार्थ से प्रेरित व्यवस्था

78 **जवरीमल्ल पारख**
तेल देखो, तेल की धार देखो

विज्ञापन की दरें

बैक कवर	5,000 रु.	25.5 x 18.0 cm
भीतर का कवर	4,000 रु.	25.5 x 18.0 cm
पूरा पेज	2,000 रु.	24.5 x 17.6 cm
आधा पेज	1,000 रु.	17.6 x 12.5 cm
चौथाई पेज	500 रु.	12.5 x 8.5 cm

संपादकीय

खामोश! हिंदू राष्ट्र बन रहा है

गुजरात में हुआ अल्पसंख्यकविरोधी कत्लेआम अगर डी फैक्टो यानी इसका एलान था, तो अयोध्या विवाद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के एडवोकेट जनरल सोली सोराबजी का हस्तक्षेप इसका डी ज्यूरे यानी विधिवत एलान है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है बल्कि काफी हद तक बन भी गया है। बेशक, यह महत्वपूर्ण है कि गुजरात में जो कुछ हुआ उसके बावजूद, आर एस एस प्रचारक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी सुरक्षित बनी हुई है। अहमदाबाद में तथा दूसरी जगहों पर, खासतौर पर विहिप के आह्वान पर तथा भाजपा के समर्थन से आयोजित बंद के दौरान 28 फरवरी को जिस तरह अल्पसंख्यकों के खिलाफ आगजनी, लूट तथा कत्लेआम की छूट दी गयी थी, उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने तथा मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने की बात तो दूर रही, मौजूदा सत्ताधारी गठजोड़ तथा सत्ताधारी भाजपा को तो नरेंद्र मोदी को इसके लिए हटाना तक मंजूर नहीं है कि उनके शासन में गुजरात का भयानकतम दंगा हुआ है, जिसने मौतों की संख्या के लिहाज से अब तक के सबसे भयानक माने जाते रहे, गुजरात के 1968 के दंगों को भी पीछे छोड़ दिया है। कानून-व्यवस्था की इतनी भारी विफलता के सामने, राज्य में राजनीतिक प्रशासन के सर्वोच्च पद पर बैठे पदाधिकारी का इस्तीफा लेने जैसे न्यूनतम शिष्टाचार की भी, जिसके कांग्रेस जैसी पार्टी के राज में कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे, भाजपा से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उल्टे खुद मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री तक, सब एक ही सुर में यह दोहराने में लगे हुए हैं कि "पहली बार गुजरात में किसी दंगे पर 72 घंटे में, सिर्फ 72 घंटे में काबू पा लिया गया"। इसके बाद तो इसी की सिफारिश करना बाकी रहता है कि नरेंद्र मोदी को "चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर" के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए।

फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि गुजरात में इतना कुछ होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं और केंद्रीय सत्ता प्रतिष्ठान बाकायदा उनके बचाव में लगा हुआ है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्रीय सत्ता प्रतिष्ठान यह समझते-बूझते हुए बल्कि वास्तव में सबसे बढकर इसीलिए मोदी का बचाव कर रहा है कि गुजरात की मोदी सरकार इस पूरे प्रसंग में, एक हिंदू सरकार की तरह, वह भी किसी उदार अर्थ में नहीं बल्कि इस शब्द के सबसे कट्टर तथा सबसे उन्मत्त अर्थ में एक हिंदू सरकार की तरह, और इसलिए अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बहुसंख्यक हिंदुओं के भी वास्तविक हितों पर भारी हमला करने वाली सरकार के तौर पर काम कर रही थी। मोदी सरकार का यह 'हिंदुत्व' कोई गोधरा की घटना की दुहाई देकर, क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया बताकर 28 फरवरी को पूरे गुजरात में जो हुआ था उसे उचित ठहराने तक ही सीमित नहीं था। मोदी सरकार का यह हिंदुत्व इस तक भी सीमित नहीं था कि खुद मुख्यमुत्री ने बड़ी दीदादिलेरी से, अहमदाबाद में अल्पसंख्यकों के कत्लेआम को दो सबसे भयानक तथा सबसे चर्चित घटनाओं को भी, हजारों लोगों की हिंसक भीड़ों के हमलों में मारे गए अल्पसंख्यकों के ही उकसावे का नतीजा बताया था। नारोडा का कत्लेआम मुख्यमंत्री के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के जान-बूझकर बहुसंख्यकों की एक भीड़ पर टैंपो चढ़ा देने की वजह से भड़का था। गुलबर्ग सोसाइटी का कत्लेआम, जिसमें कांग्रेस के पूर्व-सांसद एहसान जाफ़री पूरे छः घंटे तक टेलीफोन पर राज्य सरकार के सभी अधिकारियों से बचाने की गुहार करते रहने के बाद मारे गए थे, मुख्यमंत्री मोदी के अनुसार पूर्व-सांसद की ओर से भीड़ पर गोलियां चलाए जाने से भड़का था! मोदी सरकार का हिंदुत्व इस सबसे आगे, इसका मौका मुहैया कराने पहुंचता था कि मुसलमानों को एक जोरदार सबक सिखाया जाए।

इस "तुरंत जवाबी कार्रवाई" के जरिए, मुसलमानों को "सबक सिखाया" जा रहा था। सबक सिखाने वालों को इसका पता था कि सरकार, पुलिस व शेष प्रशासन समेत, उनके साथ है। सबक सिखाने वालों को इसका भी पता था कि यह छूट भी कोई अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकती है बल्कि चौबीस घंटे के बाद सेना तैनात हो सकती है। सबक सिखाने वालों को इसका पता था कि जो भी करना है तुरंत करना है। गुजरात में, जहां का गृहमंत्री खुद इस जिम्मेदारी को संभालने से पहले छः वर्ष तक विहिप का राज्य प्रमुख रहा था, गोधरा की घटना के विरोध में विहिप के बंद के आह्वान के खतरों को पहचानने के लिए किसी विशेष दूरंदेशी की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद, विहिप के 27 फरवरी की दोपहर तक बंद का आह्वान करने पर, शाम तक काफी सोच-विचार कर भाजपा ने इस आह्वान के लिए अपने समर्थन का एलान कर दिया। विहिप-बजरंग दल आदि का आह्वान अगर तुरंत जवाबी कार्रवाई का आह्वान था, तो इसके लिए भाजपा का समर्थन, शासन की तरफ से इस तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए छूट दिए जाने का एलान था। जाहिर है कि जिनके लिए यह एलान था, उन्होंने इसका अर्थ समझने में कोई गलती नहीं की।

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा विहिप के नेता, गोधरा में साथ-साथ थे और उनके बीच निरंतर विचार-विमर्श के क्रम में ही सारे निर्णय हो रहे थे। ये सारे निर्णय इसके बावजूद लिए जा रहे थे कि साबरमती ट्रेन पर आगजनी